

चीनी निर्यात बढ़ाने को मिल सकती है छूट

केंद्रीय मंत्रिमंडल आज उपभोक्ता एवं खाद्य मामलों के मंत्रालय के प्रस्ताव पर करेगा विचार

पीयूष पांडेय

नई दिल्ली। केंद्र सरकार चीनी निर्यात पर छूट देने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर सकती है। बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट के समक्ष यह प्रस्ताव रखा जाएगा। उपभोक्ता एवं खाद्य मामलों के मंत्रालय ने गन्ना किसानों के बकाए के जल्द भुगतान के मद्देनजर यह प्रस्ताव तैयार किया है। इसमें कुल 50 लाख टन चीनी के निर्यात पर छूट मुहैया कराने की सिफारिश की गई है।

खाद्य मंत्रालय ने हाल ही में 20 लाख टन चीनी निर्यात के लिए समय सीमा तीन माह बढ़ाकर दिसंबर तक कर दिया है। मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक अब तक केवल 5 लाख टन चीनी का निर्यात किया गया है। इसी वजह से मंत्रालय ने चीनी निर्यात पर छूट मुहैया कराने का प्रस्ताव तैयार किया है। ताकि चीनी मिले ज्यादा निर्यात करें और गन्ना किसानों के बकाए का जल्द भुगतान हो। सूत्र बताते हैं कि कैबिनेट मंत्रालय के जिस प्रस्ताव पर विचार करने वाली है, उसमें 50 लाख टन चीनी निर्यात पर छूट देने की सिफारिश शामिल



है। माना जा रहा है कि प्रति क्विंटल के हिसाब से सब्सिडी देने का प्रस्ताव रखा गया है। इसके अलावा प्रति क्विंटल यातायात सब्सिडी को भी शामिल किया गया है। तटीय इलाके की मिलों के लिए ढाई रुपए और तट से दूर वाली मिलों के लिए 3 रुपए प्रति क्विंटल यातायात सब्सिडी मुहैया कराने का प्रस्ताव है। गौरतलब है कि निर्यात में कमी का कारण कच्ची चीनी उपलब्ध नहीं होना है, जबकि वैश्विक बाजार में इसकी मांग है। उद्योग ने मंत्रालय से समय सीमा बढ़ाने का आग्रह किया है। ताकि 2018-19 सीजन से प्राप्त नई कच्ची चीनी निर्यात की जा सके।

Amar Gajala

19/9/2018